

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 84/16

मोहन पुत्र किशन जाति गुर्जर निवासी कुनकटा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
अपीलांटान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
रेस्पोंडेडान

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न० 50/14 निर्णय दिनांक
28.5.14 एवं नायब तहसीलदार तलावडा मु०न० 864/13 निर्णय दिनांक 26.9.13)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री श्याम मोहन शर्मा
2. रेस्पोंडेडान की ओर से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 30.09.2019

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु०न० 50/14 निर्णय दिनांक 28.5.14 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा के प्रकरण संख्या 864/13 दिनांक 26.9.13 के विरुद्ध पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर में अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार तलावडा के निर्णय दिनांक 26.9.13 के विरुद्ध प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि ग्राम कुनकुटा खुर्द में स्थित आराजी खसरा न० 326/1136 रकबा 0.55 किस्म गैर मुमकिन नदी पर सम्मत 2070 खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर काश्त करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्धदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व फसल जप्त करने के साथ साथ अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की गई थी। अति० जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार तलावडा के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेडान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील में बताया कि तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय रुयेदार मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों से परे होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख०न० 326/1136 के 55 ऐयर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए दो माह का सिविल कारावास एवं शास्ति एवं बेदखली से दण्डित किये जाने के आदेश

विधि विरुद्ध पारित किया गया है। अपीलांत द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। तथा अपीलांधीन निर्णय अपीलांत की विधिवत तामिल हुए बिना एक पक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर ही अपीलांधीन निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई सबूत एवं दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे अपीलांत का उक्त आराजीयात पर फ़्यातवर्ती अतिक्रमण सिद्ध होता हो। केवल मात्र पटवारी हल्का के बयान खाली प्रपत्र पर खाना पूर्ति कर भरे गये हैं जिसमें कोई असलियत नहीं है। इसी प्रकार पूर्व में पारित भौतिक बेदखी के वक्त उपस्थित रिपोर्ट के बयान रिकार्ड पर लिये गये हैं। ना ही कोई स्वतंत्र साक्ष्य कराई गई है एवं पटवारी हल्का से अपीलांत को जिरह का कोई अवसर दिया गया है। इस प्रकार अपीलांत को केवल मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर फ़्यातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास एवं शास्ति एवं बेदखली के दण्डित किया गया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः अपीलांत की अपील स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त फरमाया जावे।


रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील में बताया कि अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा फ़्यातवर्ती अतिचार के संबंध में सम्यक जाँच करने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। अपीलांत द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है, जो सार्वजनिक लोककल्याणकारी कार्य के प्रयोजन में आती है जिसका कभी भी नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलांत द्वारा अतिक्रमित भूमि का रकबा काफी बड़ा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अतिक्रमी का यह अतिक्रमण काफी पुराना है। अपीलांत द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की जाँच पटवारी हल्का के अलावा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अपीलांत का यह कथन मिथ्या है कि अपीलांत को बिना सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांत सारहीन रूप से खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षों की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलांत द्वारा सम्वत 2070 में ग्राम अमरगढ की आराजी ख0न0 326/1136 रकबा 0.55 ऐयर भूमि पर जोत लगाकर बाजरे की फसल कस्त की गई है। जो कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.9.13 से स्पष्ट है एवं नकल खसरा परिवर्तित निर्धारण प्रपत्र संख्या प.14 सम्वत 2069 वर्ष 2012 में भी अतिचार दर्शित है। मुताबिक रिपोर्ट अतिक्रमित भूमि गैर मुमकिन नदी है। जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आती है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटिशन नं0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय

दिनांक 02.08.2004 मे नदी,नाला,तालाब आदि के संरक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया है। जबकि पत्रावली मे उपलब्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 12.9.13 को नोटिस जारी कर 26.9.13 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसकी तामिल तामिल कुन्निदा द्वारा चर्यादगी से कराई गई है जिस पर दो स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलांट द्वारा दिनांक 26.9.13 को अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर भी पश्चातवर्ती अतिचार नही करने संबंधी कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। जिससे उसका अतिचार नही करना सिद्ध हो सके एवं पटवारी हल्का से उसे जिरह का अवसर दिया जा सके। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत एवं सम्यक जांचोपरान्त ही पारित किये गये है। जिनमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः हमारे मतानुसार दोनो अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णयो मे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति०जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के मु०न० 50/14 निर्णय दिनांक 28.5.14 एवं नायब तहसीलदार तलावडा तहसील गंगापुर सिटी के मु०न० 864/13 निर्णय दिनांक 26.9.13 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।


30.9.19
(बी०एल० समण) सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी

